विचार बिन्दु

अपना नाम सदा कायम रखने के लिए मनुष्य बड़े से बड़ा जोखिम उठाने, धन खर्च करने, हर तरह के कष्ट सहने, यहाँ तक कि मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। –सुकरात

पेयजल लाइनों में लीकेज सुधार और हैंडपंप रखरखाव सरकार की संवेदनशीलता का परिचायक

जनता के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए राजस्थान सरकार ने गर्मी का मौसम शुरु होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता व पेयजल साधनों खासतौर से पाइपलाइन व हैंडपंपों के रखरखाव व मरम्मत का कार्य दो दिन का अभियान चलाकर करके सरकार की सजगता का परिचायक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि राज्यव्यापी विशेष अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में चलाते हुए पानी से जुड़ी सभी योजनाओं यथा जल जीवन मिशन, अमृत योजना और ग्रीष्मकालीन कन्टीजेंसी कार्यों को अभियान के दायरे में लाया गया। अब तक का अनुभव यह रहा है कि गर्मी का मौसम आते-आते स्थानीय प्रशासन और सरकार दोनों के सामने ही पानी-बिजली की समस्या होती आई है। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में पानी-बिजली की समस्या अधिक गंभीर होती है। एक तरफ तापमान में बढ़ोतरी, दूसरी तरफ शहरों-गांवों में बिजली की मांग बढ़ने और अत्यधिक मांग वृद्धि के कारण बिजली कटौती ऐसी समस्या हो जाती है जो लाख प्रयास करने पर भी अपना असर दिखा ही देती है। बिजली से भी अधिक समस्या पानी, खासतौर से पीने के पानी की होती है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और जलदाय विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के सामने गंभीर चुनौती उभर जाती है। हांलाकि इस समस्या को समय रहते प्लान बनाकर पूरी तरह तो नहीं पर काफी हद तक कम करके आमजन को राहत दी जा सकती है। यही कारण है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर समूचे प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर 18 और 19 अप्रेल को दो दिवसीय राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाकर पाइपलाइनों के लीकेज से लेकर खराब हैंडपंपों के सुधार तक के कार्य को किया जाना सरकार की आमजन के प्रति गंभीरता का परिचायक है।

> **प्रदेशभर में जल जीवन मिशन, अमृत, ग्रीष्मकालीन कंटीन्जेंसी कार्यो, क्षतिग्रस्त पाईप लाइनों एवं हैण्डपम्पों का जिला प्रशासन एवं जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा सघन निरीक्षण का अभियान चलाया गया और अभियान के दौरान हजारों स्थानों पर पाईप लाईन लीकेज व हैंडपंपों की मरम्मत कर ठीक किया गया। 18 एवं 19 अप्रेल को संचालित राज्यव्यापी विशेष अभियान में जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं खण्ड विकास अधिकारियों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के तकनीकी अधिकारियों के साथ गांव-गांव जाकर कार्यो को देखा और लीकेज व खराब पाइपलाइनों, हैंडपंपों को मौके पर ही मरम्मत कार्य करवाया गया ताकि गर्मी में गांववासियों को असुविधा ना हो।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए प्रतिबद्धता को इसी से समझा जा सकता है कि प्रदेशभर में जल जीवन मिशन, अमृत, ग्रीष्मकालीन कंटीन्जेंसी कार्यों, क्षतिग्रस्त पाईप लाइनों एवं हैण्डपम्पों का जिला प्रशासन एवं जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा सघन निरीक्षण का अभियान चलाया गया और अभियान के दौरान हजारों स्थानों पर पाईप लाईन लीकेज व हैंडपंपों की मरम्मत कर ठीक किया गया। 18 एवं 19 अप्रेल को संचालित राज्यव्यापी विशेष अभियान में जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं खण्ड विकास अधिकारियों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के तकनीकी अधिकारियों के साथ गांव-गांव जाकर कार्यों को देखा और लीकेज व खराब पाइपलाइनों, हैंडपंपों को मौके पर ही मरम्मत कार्य करवाया गया ताकि गर्मी में गांववासियों को असुविधा ना हो। सरकार का दावा है कि अभियान के अन्तर्गत 2677 कार्यों का निरीक्षण किये गये, जिनमें जल जीवन मिशन के 407, अमृत योजना के 80, ग्रीष्मकालीन कंटीन्जेंसी के 77 कार्य एवं अवरूद्ध हैण्डपम्प, क्षतिग्रस्त पाइपलाइन आदि के कार्य करवाये गये। ग्रामीणों द्वारा दर्ज 2792 शिकायतों में से 2775 शिकायतों को तकनीकी कर्मचारी एवं अभियन्ताओं की लगभग 450 टीमों द्वारा निराकरण किया गया। सरकार का दावा है कि इनमें 1535 हैण्डपम्प मरम्मत, 911 पाइपलाइन लीकेज सुधार एवं 329 अन्य सुधार कार्य शामिल है।

आंकड़ों पर नहीं भी जाया जाएं तो इस दो दिवसीय अभियान से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार गर्मी के मौसम में पानी की सुचारु व्यवस्था को लेकर गंभीर है। इसके साथ ही जब सरकार का मुखिया स्वयं संवेदनशील होता है तो फिर उसका मैसेज नीचले स्तर तक अवश्य जाता है और यही कारण है कि गर्मी को देखते हुए जल प्रबंधन से जुड़े पीएचईडी विभाग सहित संबंधित विभाग चुस्त दुरुस्त होकर जुट गए हैं। मुख्यमंत्री और सरकार की मंशा भी अब स्पष्ट हो गई है ऐसे में फील्ड स्तर पर किसी तरह की कोताही की संभावनाएं नगण्य रह जाती है। पीएचईडी और जल संसाधन से जुड़े फील्ड अधिकारियों को गर्मी के मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भावनाओं और मंशा के अनुसार अति सक्रिय होकर पानी की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुस्तेद रहना होगा। ग्रामीणों और आमनागरिकों को भी पानी की एक एक बूंद को सहेजने का संकल्प लेना होगा क्योंकि एक एक बूंद पानी की बचत से हम जरुरतमंद अन्य लोगों तक पानी उपलब्ध कराने में अपना योगदान दे सकेंगे। पानी का किसी भी तरह से दुरुपयोग या अनावश्यक उपयोग नहीं होना चाहिए, यह हम सबकी जिम्मेदारी हो जाती है। पानी की उपलब्धता के पावन कार्य में प्रत्येक नागरिक की अपनी भूमिका होती है और हमें हमारी जिम्मेदारी को जिम्मेदार नागरिक के रुप में निभानी होगीं।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)

राशिफल गुरूवार 30 अप्रैल, 2026

पंडित अनिल शर्मा

वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, चतुरदशी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2083, चित्रा नक्षत्र रात्रि 2:17 तक, वज्र योग रात्रि 8:55 तक, गर करण प्रातः 8:32 तक, चन्द्रमा आज दिन 1:14 से तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-मेष, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-मीन, बुध-मीन, गुरू-मिथुन, शुक्र-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज रवियोग रात्रि 2:17 तक है। भद्रा रात्रि 9:13 से आरम्भ होगी। आज बुध अश्विनी मेष राशि में प्रातः 6:52 पर प्रवेश करेगा। आज छिन्न माता जयन्ती, श्री नृसिंह जयन्ती और व्रत है। आज श्री आद्यशंकाराचार्य कैलाश गमन है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः शुभ सूर्योदय से 7:31 तक, चर 10:46 से 12:24 तक, लाभ-अमृत 12:24 से 3:39 तक, शुभ 5:17 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 1:00 से 3:00 तक। सूर्योदय 5:53, सूर्यास्त 6:55

मेष
व्यक्तिगत पारिवारिक परेशानियां दूर होने लगेगी। परेशानियां दूर होने लगेगी। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

सिंह
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेगी।

धनु
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

कन्या
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

मकर
परिवार में शुभ-मांगलिक संदेश प्राप्त होंगे। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है। आज अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।

मिथुन
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

तुला
व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आज घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। समय अनर्गल कार्यों में खराब होगा।

कुंभ
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

कर्क
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज व्यक्तिगत प्रयासों और मित्रों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी।

वृश्चिक
अपने आर्थिक मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक विवादों का निपटारा हो सकता है। दिन के मध्यान्ह पश्चात यात्रा संभव है।

मीन
परिवार में आपसी सहयोग बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। दिन के मध्यान्ह पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है।

भारत में दूध की सच्चाई : उत्पादन का सम्राट या मिलावट का साम्राज्य?

सुनील दत्त गोयल

कपूरे विश्व में लोग ऐसा मानते हैं कि भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। यह धारणा दशकों से दोहराई जाती रही है और इतनी बार दोहराई गई है कि अब इसे बिना सवाल किए सच मान लिया गया है। लेकिन जब हम इस दावे को तथ्यों और जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर परखते हैं, तो तस्वीर उतनी चमकदार नहीं दिखती। हाँ, यह सही है कि भारत का कुल दूध उत्पादन लगभग 248 मिलियन टन के आसपास बताया जाता है और करीब 8.9 करोड़ लोग इस क्षेत्र से जुड़े हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह पूरा दूध वास्तव में शुद्ध है, या हम केवल आंकड़ों के भ्रम में जी रहे हैं।

भारत में पशुओं की संख्या बहुत अधिक है – लगभग 30 करोड़ के आसपास। पहली नजर में यह संख्या गर्व करने योग्य लगती है, लेकिन जब हम इसे तोड़कर देखते हैं, तो सच्चाई सामने आती है कि इनमें से केवल 13-14 करोड़ पशु ही किसी समय दूध दे रहे होते हैं। बाकी या तो सूखे (ड्राई) होते हैं, या उत्पादन में शामिल नहीं होते। इसका मतलब यह है कि हम वास्तविक उत्पादन क्षमता से अधिक संख्या का प्रचार कर रहे हैं। यह एक ऐसा भ्रम है जो न केवल नीति-निर्माताओं को बल्कि आम जनता को भी गुमराह करता है।

जब हम भारत के डेयरी सेक्टर की तुलना विकसित देशों से करते हैं, तो अंतर और स्पष्ट हो जाता है। भारत में लगभग 14 करोड़ दूध देने वाले पशु हैं, जबकि अमेरिका में केवल लगभग 90 लाख। इसके बावजूद अमेरिका लगभग 100 मिलियन टन दूध उत्पादन करता है। इसका मतलब यह है कि भारत में उत्पादन संख्या के बल पर है, जबकि विकसित देशों में यह दक्षता, प्रबंधन और तकनीक के आधार पर है। भारत में प्रति पशु उत्पादन बहुत कम है, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है।

हम गायों को 'माता' का दर्जा देते हैं। यह भावनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत बड़ा स्थान है। लेकिन क्या हम वास्तव में उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं जो 'माँ' शब्द के साथ आती है? माँ का मतलब केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवनभर देखभाल, पोषण और सुरक्षा होता है। बल्कि यह कहना उचित होगा कि हम गौ माँ के साथ रहते हैं और वो जीवन भर हमारा भरण पोषण करती हैं। भारतीय संस्कृति में गायों को माँ का दर्जा इसीलिए दिया गया है क्योंकि उनके बिना परिवार चल ही नहीं सकता था, गाय के दूध से ही दही, घी, मक्खन इत्यादि बनता था जिससे पूरे परिवार का पोषण होता था और अतिरिक्त दुग्ध उत्पादों को बेचकर गुजारा चल जाता था। वास्तविकता यह है कि अधिकांश दुधारू पशुओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है, वह इस सम्मान के बिल्कुल विपरीत है।

दुग्ध उत्पादक सुबह दूध निकालने के बाद अक्सर पशुओं को खुले में छोड़ देते हैं। उन्हें न तो संतुलित आहार मिलता है और न ही पर्याप्त पानी। जबकि वैज्ञानिक रूप से यह स्थापित है कि एक दुधारू पशु को दिन भर में कम से कम 60 लीटर पानी पीने के लिए चाहिए और 30 से 40 लीटर अन्य आवश्यक क्रियाओं के लिए। इसके अलावा, पशु के वजन के अनुसार हरा चारा, सूखा चारा और पोषक आहार देना जरूरी है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं किया जाता।

पशुओं का समय पर टीकाकरण, कृमिनाशक दवाइयाँ, नियमित स्वास्थ्य जांच – ये सब डेयरी प्रबंधन के मूल स्तंभ हैं। लेकिन इनका पालन बहुत सीमित स्तर पर होता है। दुधारू पशुओं का समय पर गर्भाधान और गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त पोषण देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह पूरी प्रक्रिया इतनी संवेदनशील होती है कि इसकी तुलना घर में एक गर्भवती महिला की देखभाल से की जा सकती है। लेकिन व्यवहार में यह संवेदनशीलता कहीं दिखाई नहीं देती।

मैं यह बातें केवल सैद्धांतिक रूप से नहीं कह रहा हूँ। मैंने स्वयं भीलवाड़ा के ठाम रायला तहसील बनेड़ा में 2006 से 2012 तक लगभग 500 गायों का डेयरी फार्म चलाया है। मैंने इस सिस्टम को अंदर से देखा है, जिया है। बड़े सपने थे कि आधुनिक डेयरी मॉडल स्थापित किया जाएगा, लेकिन बैंकों, स्थानीय छुटभैये नेताओं, जाति और धर्म के ठेकेदारों और सलाहकारों के भ्रष्टाचार ने सब कुछ खत्म कर दिया। करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ और अंततः 500 गायों को मुफ्त में देकर फार्म बंद करना पड़ा। जमीन बेचकर कर्ज चुकाना पड़ा। यह केवल व्यक्तिगत विफलता नहीं थी, बल्कि सिस्टम की विफलता का परिणाम था। जबकि मेरा यह पूरा प्रोजेक्ट जर्मनी एवं स्वीडन की बहुत बड़ी कंपनियों के तकनिकी सहयोग से चल रहा था। इसकी पूरी जानकारी मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अब सबसे महत्वपूर्ण और असहज सवाल – त्योहारों के दौरान अचानक दूध कहाँ से आता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ साल भर त्योहार, शादियाँ, भंडारे और सामाजिक आयोजन चलते रहते हैं। इन अवसरों पर दूध और डेयरी उत्पादों एवं मिठाइयों की मांग अचानक 2 से 4 गुना तक बढ़ जाती है। यह एक सामान्य आर्थिक व्यवहार है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि इस मांग को पूरा कैसे किया जाता है। क्या पशु अचानक ज्यादा दूध देने लगते हैं? क्या उनके शरीर में कोई ऐसा तंत्र है जो मांग के अनुसार उत्पादन बढ़ा देता है? नहीं। यह पूरी तरह जैविक प्रक्रिया है और इसे अचानक बढ़ाया नहीं जा सकता। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि बड़ी कंपनियाँ अतिरिक्त दूध को मिल्क पाउडर (एश्ङ) में बदलकर स्टोर करती हैं और जरूरत पड़ने पर उसे फिर से उपयोग में लाती हैं। यह तर्क आंशिक रूप से सही है और संगठित डेयरी सेक्टर में ऐसा होता भी है।

यह सोच का विषय है की कभी सुनने में नहीं आया की भारत में कभी दूध की कमी हो गई हो या कभी घरों में दूध देने आने वाले लोगों ने कहा हो की अगले कुछ दिनों तक मेरे यहाँ दूध का उत्पादन कम रहेगा।

लेकिन भारत का लगभग 60 प्रतिशत डेयरी सेक्टर असंगठित है। और यहीं पर सबसे बड़ा खेल चलता है। जब मांग बढ़ती है, तो सप्लाई को एडजस्ट किया जाता है। यह एडजस्टमेंट वैज्ञानिक तरीके से नहीं, बल्कि मिलावट, सिंथेटिक दूध और घटिया गुणवत्ता के माध्यम से होता है। यही वह ग्रे ज़ोन है जिसे कोई खुलकर स्वीकार नहीं करता, लेकिन जो वास्तविकता में मौजूद है।

मिलावटी और नकली दूध के बीच का अंतर समझना जरूरी है।

मिलावटी दूध में असली दूध होता है, लेकिन उसमें पानी या अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं।

नकली दूध पूरी तरह रसायनों से तैयार किया जाता है। आज बाजार में दोनों प्रकार के उत्पाद मौजूद हैं और उपभोक्ता को इसका पता भी नहीं चलता।

मिलावट का स्तर इतना बढ़ चुका है कि अब यह केवल पानी तक सीमित नहीं है।

यूरिया और डिटर्जेंट का उपयोग दूध को गाढ़ा और झागदार दिखाने के लिए किया जाता है।

स्टार्च और ग्लूकोज मिलाकर उनका घनत्व बढ़ाया जाता है।

हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फॉर्मेलिन जैसे रसायनों का उपयोग उसे खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। यह सब मिलकर एक ऐसा केमिकल कॉकटेल बनाते हैं, जिसे हम रोजाना पी रहे हैं।

इनका असर धीरे-धीरे शरीर पर पड़ता है। किडनी, लिवर, हार्मोनल सिस्टम और अंततः कैंसर जैसी गंभीर बीमारियाँ इससे जुड़ी हुई हैं। यह एक धीमा जहर है, जो तुरंत असर नहीं दिखाता, लेकिन लंबे समय में शरीर को नुकसान पहुँचाता है।

2020 का कोरोना लॉकडाउन इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा परीक्षण था। जब होटल, हलवाई, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक कार्यक्रम पूरी तरह बंद थे, तब दूध की मांग अचानक गिर गई। यह एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है कि जब खपत नहीं थी, तो अतिरिक्त दूध कहाँ चला गया। क्या पशुओं ने अचानक दूध देना बंद कर दिया था?

दूध से बने उत्पादों की स्थिति और भी चिंताजनक है। पनीर, मावा, दही और मिठाइयाँ – इनमें मिलावट का स्तर और अधिक होता है। अनुमान यह बताते हैं कि इन उत्पादों का 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा सब-स्टैंडर्ड या नकली हो सकता है। इसके बावजूद इनका उपभोग बिना किसी जांच या सवाल के किया जा रहा है।

ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का उपयोग इस समस्या को और गंभीर बनाता है। यह इंजेक्शन दूध निकालने के लिए उपयोग किया जाता है और भारत में प्रतिबंधित है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह आज भी आसानी से उपलब्ध है। एक ही इंजेक्शन कई पशुओं में लगाया जाता है, जिससे कृत्रिम रूप से दूध निकाला जाता है। इसके दुष्प्रभाव केवल पशुओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ते हैं।

गौशालाओं की स्थिति भी इस समस्या का हिस्सा है। दान तो बहुत होता है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं होता। चारा कागजों में ही खत्म हो जाता है और पशु कुपोषित रहते हैं। धार्मिक आस्था के नाम पर गलत प्रथाएँ अपनाई जाती हैं, जिससे स्थिति और खराब होती है।

भारत में दानदाताओं के द्वारा अनाप-शनाप खर्च करने की वजह से बाजार में हरे और सूखे चारे की बेवजह मांग बन जाती है और चारे के दाम बढ़ जाते हैं। इस वजह से किसान और अन्य जो पशुपालक हैं, वे महंगा चारा खरीद नहीं पाते और कंजूसी करने लगते हैं। परिणामस्वरूप उनके जानवर अंदर से कमजोर, कुपोषित और दुबले हो जाते हैं। इस प्रकार दान-धर्म के नाम पर वास्तव में उनके साथ अनर्थ हो रहा है।

जो लोग वास्तव में अपना डेयरी फार्म चला रहे हैं या दुग्ध उत्पादन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी महंगे चारे के कारण लागत बहुत बढ़ जाती है, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बन पाती और अंततः वे डेयरी फार्म बंद करने पर मजबूर हो जाते हैं।

मेरा सरकार को यह सुझाव है कि यदि सरकार चाहती है कि पूरे देश में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध दूध उपलब्ध हो तो उसे कॉर्पोरेट डेयरी फार्मिंग पर स्पष्ट और प्रभावी नीति बनानी चाहिए। अभी तक सरकार की जो भी डेयरी से संबंधित नीतियां चल रही हैं, वे वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार पर्याप्त नहीं हैं। यदि हम चाहते हैं कि नवयुवक डेयरी फार्मिंग में आएं, तो इस क्षेत्र को आधुनिक तकनीक और व्यवस्थाओं से सुसज्जित करना होगा। जिस प्रकार विदेशों में 5000 से 25000 पशुओं तक के डेयरी फार्म सामान्य रूप से संचालित होते हैं, उसी प्रकार भारत में भी बड़े स्तर पर डेयरी फार्मिंग को प्रोत्साहित करना होगा। यहां तक कि खाड़ी देशों में, जहां पानी की भारी कमी है और चारों ओर रेगिस्तान है, वहां भी 50,000 से अधिक पशुओं वाले डेयरी फार्म सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं और अपने ब्रांड के तहत सभी डेयरी उत्पादों का उत्पादन और वितरण कर रहे हैं।

सरकारी तंत्र की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। कई अधिकारी ऐसे पदों पर हैं जिनके पास न तो व्यावहारिक ज्ञान है और न ही वास्तविक अनुभव। वेटरनरी सिस्टम कमजोर है, बैंकिंग सिस्टम में गलत निर्णय लिए जाते हैं और पूरी व्यवस्था केवल कागजों पर चलती है। यही कारण है कि डेयरी सेक्टर में निवेश का जोखिम बढ़ जाता है और योग्य लोग इससे दूर रहते हैं।

जितने भी राज्य स्तरीय सरकारी सहकारी डेयरी कॉर्पोरेशन हैं, उनमें व्याप्त आकंठ भ्रष्टाचार के कारण निजी क्षेत्र का विकास बाधित हो रहा है। सरकार सस्ता दूध उपलब्ध कराने की मजबूरी में गुणवत्ता से समझौता करती दिखती है, और कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि भले ही वह दूध संदिग्ध या नकली ही क्यों न हो, उसे बाजार में बनाए रखा जाता है। इस वातावरण में कॉर्पोरेट डेयरी फार्म के लिए टिकना या विकसित होना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि वे न तो भ्रष्ट तंत्र से प्रतिस्पर्धा कर पाते हैं और न ही उन्हें लागत के अनुरूप उचित मूल्य मिल पाता है।

आज बड़े-बड़े ब्रांड हजारों लीटर दूध का उपयोग करते हैं। कई जगह 50,000 लीटर प्रतिदिन तक की खपत होती है, लेकिन उनका दूध कभी खराब क्यों नहीं होता, यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। क्या इनकी कभी गहन जांच हुई है? क्या सरकार इस पर जवाबदेही तय करेगी?

भारत पहले ही डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मामलों में अग्रणी देशों में शामिल है और अब तेजी से कैंसर की ओर बढ़ रहा है। मिलावटी दूध और खाद्य पदार्थ इस बढ़ते स्वास्थ्य संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

यदि भारत सरकार वास्तव में चाहती है कि देश में डेयरी उत्पादन पारदर्शी हो और घोटाले-घपले बंद हों, तो अब समय आ गया है कि वर्तमान सहकारी ढांचे से आगे बढ़कर डेयरी सेक्टर को कॉर्पोरेट डेयरी प्रोसेसिंग मॉडल की दिशा में परिवर्तित किया जाए। इसके लिए मौजूदा कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन सिस्टम में प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट के तहत आवश्यक सुधार कर निर्णायक कदम उठाने होंगे। पारंपरिक पाश्चरीकृत दूध की बिक्री के बजाय अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट (ळपऊ) तकनीक अपनाकर दूध को पूरी तरह स्टेरिलाइज किया जाए और उसे एसेप्टिक पैकेजिंग में बाजार में उपलब्ध कराया जाए।

इससे दूध की शेल्फ लाइफ 30 से 180 दिन तक बढ़ सकती है, ठीक उसी तरह जैसे आज पैकेज्ड फ्रूट जूस उपलब्ध होता है। यह व्यवस्था न केवल लॉजिस्टिक्स को सरल बनाएगी, बल्कि कैरेट चोरी, दैनिक कलेक्शन-डिस्ट्रिब्यूशन में होने वाली गड़बड़ियों और बड़े पैमाने पर होने वाले भ्रष्टाचार को भी समाप्त कर सकती है।

अनुमान है कि इस बदलाव से सरकार को हर साल 20-25 हजार करोड़ रुपये तक की बचत हो सकती है, और आम जनता को हर समय सुरक्षित एवं उपलब्ध दूध मिल सकेगा। निष्कर्ष स्पष्ट है – जिस दिन यह प्रणाली पूरी तरह लागू हो जाएगी, उस दिन भारत में वास्तव में दूध की नदियाँ बहती हुई दिखाई देंगी।

अंत में सच्चाई यही है कि भारत दूध उत्पादन में नंबर 1 जरूर है, लेकिन गुणवत्ता के मामले में स्थिति बेहद चिंताजनक है। यह पूरा सिस्टम असली दूध, प्रोसेस्ड दूध और मिलावटी दूध के मिश्रण पर चल रहा है। उपभोक्ता को यह समझ ही नहीं आ रहा कि वह क्या खरीद रहा है और क्या खा रहा है।

मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि केवल सस्ता देखकर दूध न खरीदें, बल्कि उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाएँ। यह केवल सरकार या उद्योग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह जागरूक बने। क्योंकि अंत में सच्चाई यही है –

दूध अमृत भी हो सकता है... और एक संगठित जहर भी।

–रोटेरियन सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला: स्वाद, संस्कृति और सहकारिता का अनूठा संगम

पिंक सिटी की फिजाओं में महकती है मसालों की महक

दिनेश कुमार शर्मा

सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉनफेड) द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला अब जयपुर की विशिष्ट पहचान बन रहा है। हर साल अप्रेल-मई माह में जब मसाला मेले का आयोजन किया जाता है तो जयपुर की फिजा देश-प्रदेश के मसालों की खुशबू से महकती है। स्वाद, संस्कृति और सहकारिता के अनूठे संगम इस मेले के माध्यम से सहकारी समितियों को अपने व्यवसाय में वृद्धि का उचित प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध होता है।

राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है, जो वर्ष 2003 से निरन्तर सहकार मसाला मेले का आयोजन करते हुए उपभोक्ताओं को शुद्ध मसाले व अन्य उत्पाद उपलब्ध कराने की पहल करता आ रहा है। राष्ट्रीय स्तर के इस मसाला मेले का जयपुरवासियों को खास इंतजार रहता है। मेले में विभिन्न राज्य की सहकारी संस्थाओं के साथ ही राज्य की सहकारी संस्थाओं द्वारा भागीदारी की जाती है। उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही इस मेले के आयोजन से लाभान्वित होते हैं तथा जयपुरवासियों को शुद्ध मसालों सहित अन्य गुणवत्तापूर्ण उत्पाद एक ही स्थान पर उपलब्ध हो पाते हैं।

इस बार जवाहर कला केन्द्र के दक्षिण परिसर में 17 से 26 अप्रेल तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन किया गया। दस दिन के इस आयोजन में जयपुरवासियों का जबर्दस्त उत्साह देखने को मिला तथा उन्होंने जमकर मसालों और अन्य उत्पादों की खरीददारी की।

उपलब्धियों के नये आयाम- सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दक के मार्गदर्शन एवं शासन सचिव, सहकारिता डॉ. समित शर्मा के निर्देशन में दस दिवसीय इस आयोजन ने न केवल जयपुरवासियों को देशभर के उत्कृष्ट मसालों और पारंपरिक उत्पादों से रूबरू कराया बल्कि सहकारिता आधारित विपणन की सफलता का प्रभावशाली उदाहरण भी प्रस्तुत किया। मेले में इस बार लगभग 5.50 करोड़ रुपये के मसालों और अन्य उत्पादों की रिकॉर्ड बिक्री हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब सवा करोड़ रुपये अधिक रही। यह उपलब्धि अब तक की सर्वाधिक बिक्री के रूप में दर्ज हुई, जिसने मेले की लोकप्रियता और विश्वास को और सुदृढ़ किया। मेले में पहली बार लगभग 160 स्टॉल्स पर उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शनी की व्यवस्था की गई, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है और पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 40 अधिक है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए पहली बार ट्रॉली सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे खरीदारी का अनुभव और सहज बना। जन-जागरूकता के उद्देश्य से पहली बार जेनेरिक मेडिसिन जागरूकता स्टॉल लगाई गई। वहीं, आर्गेनिक उत्पाद, श्री अन्न उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद तथा जीआई टैग उत्पादों को एक ही मंच पर उपलब्ध कराकर मेले को विशिष्ट पहचान दी गई। ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं कृषक उत्पादक संगठनों की प्रभावी भागीदारी ने मेले को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारिता सशक्तीकरण से भी जोड़ा।

देशभर के उत्पादों ने बिखेरा स्वाद और विविधता का रंग- मेले में देश के विभिन्न राज्यों से आए मसाले और पारंपरिक उत्पाद उपभोक्ताओं के आकर्षण का केंद्र बने। केरल की काली मिर्च और लौंग, इरोड की हल्दी और दालचीनी, कश्मीर की केसर और ड्राई फ्रूट्स, पंजाब के चावल, मध्यप्रदेश का सिहोरी गेहूं, मथानिया की लाल मिर्च, नागौर का जीरा, रामगंजमंडी का धनिया, प्रतापगढ़ की हींग, जालोर की ईसबगोल, पुष्कर का गुलकंद, नाथद्वारा की ठण्डाई, बीकानेर के पापड़ सहित अनेक उत्पादों ने लोगों को खूब आकर्षित किया।

सहकारी संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार श्री अन्न आधारित उत्पादों को भी उपभोक्ताओं ने विशेष पसंद किया। वहीं मोबाइल चक्की के माध्यम से निशुल्क हाथों-हाथ मसाले पिसवाने की सुविधा ने मेले को और अधिक उपयोगी व आकर्षक बनाया।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मोहा मन, लक्की विनर्स को मिले पुरस्कार- मेले में प्रतिदिन अलग-अलग संभागों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। इन प्रस्तुतियों ने आगन्तुकों को भाव-विभोर किया और मेले की भव्यता में चार चांद लगाए। मेले में आगन्तुक ग्राहकों के लिए प्रतिदिन लक्की ड्रॉ एवं समापन पर मेगा बम्पर ड्रॉ की व्यवस्था भी की गई। प्रतिदिन तीन लक्की ड्रॉ निकाले गए, जिनमें प्रथम पुरस्कार में 5100 रुपये, द्वितीय पुरस्कार में 3100 रुपये एवं तृतीय पुरस्कार में 2100 रुपये का श्रीअन्न-मसाला गिफ्ट हैम्पर दिया गया। इसी प्रकार, मेले के समापन में हुए मेगा बम्पर ड्रॉ में प्रथम पुरस्कार में स्मार्ट टीवी, द्वितीय पुरस्कार में डबल डोर फ्रिज तथा तृतीय पुरस्कार में आटा मिलेट चक्की विजेताओं को दी गई।

सहकारिता की सफलता का सशक्त उदाहरण- राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला केवल एक व्यापारिक आयोजन नहीं बल्कि सहकारिता, स्थानीय उत्पादों, किसानों और उपभोक्ताओं के बीच मजबूत सेतु के रूप में उभरा है। रिकॉर्ड बिक्री, नवाचार, व्यापक सहभागिता और जन-उत्साह के साथ इस वर्ष का मेला यह सिद्ध करता है कि सहकारिता के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान देने की दिशा में यह आयोजन एक प्रभावी मंच बन चुका है। यह मेला वास्तव में 'सहकार से समृद्धि' की भावना को साकार कर रहा है।

–दिनेश कुमार शर्मा,
एपीआरओ, सहकारिता विभाग